अंतिम चरण में भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता

जल्द मिलेगी नई आर्थिक रफ्तार बोले मंत्री पीयूष गोयल

व्यापार, निवेश, तकनीक रक्षा क्षेत्र में खुलेंगे नए अवसर

मैड्रिड/नई दिल्ली, 14 जुलाई. भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित भारत-स्पेन बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-ईयू एफटीए की कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में यह समझौता लागू होने की उम्मीद है.

गोयल ने भारत और स्पेन के संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें भारत और स्पेन की साझेदारी को 'बहुआयामी और जीवंत' बताया गया है. उन्होंने कहा कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था और आर्थिक सहयोग के प्रति समान सोच रखते हैं. हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं और भारतीय उद्योग जगत भी स्पेन में निवेश के नए अवसर तलाश रहा है.

उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा, रक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देगा. पीयूष गोयल ने बताया कि इस वर्ष जनवरी में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए को अंतिम रूप दिया गया था. फिलहाल समझौते की कानूनी समीक्षा (लीगल स्क्रबिंग) अंतिम चरण में है, जो अगले एक-दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है. इसके बाद औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी कर समझौते को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत-यूके एफटीए के लागू होने के बाद भारत-ईयू समझौता भी तेजी से प्रभावी होगा और वर्ष 2026 की पहली तिमाही तक इसके लागू होने की उम्मीद है. वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इस समझौते को यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है और भारत में भी इसे लेकर व्यापक सहमति है.

उनके अनुसार, यह समझौता दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक समूहों को और अधिक मजबूती से जोड़ेगा, जिनकी वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इससे दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ-साथ निवेश, पर्यटन, अंतरिक्ष, संस्कृति और रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा.

13 जुलाई तक प्रत्यक्ष कर संग्रह रु. 7.73 लाख करोड़

नयी दिल्ली, 14 जुलाई चालू वित्त वर्ष में 01 अप्रैल से 13 जुलाई तक प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16.11 प्रतिशत बढ़कर 7,73,682 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. आयकर विभाग की वेबसाइट पर मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 13 जुलाई तक कुल गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह 4,11,854 करोड़ रुपये और कॉर्पोरेट कर संग्रह 3,35,386 करोड़ रुपये रहा. प्रतिभूतियों के लेनदेन पर कर से 26,429 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है जबकि अन्य कर प्राप्ति 12.65 करोड़ रुपये दर्ज की गयी. सरकार ने इस दौरान 1,22,491.87 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. यह पिछले साल की इसी अवधि से 14.57 फीसदी अधिक है.

वित्तीय क्षेत्र पर साइबर हमलों का बड़ा खतरा

वैश्विक औसत से 1.6 गुना अधिक हमले

डेटा सेंध का पता लगाने में लग रहे 263 दिन

नई दिल्ली, 14 जुलाई. भारत का बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र तेजी से बढ़ते साइबर खतरों की चपेट में है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कंप्यूटर आपात कालीन प्रतिक्रिया दल सीएसआईआरटी-फिन और साइबर सुरक्षा कंपनी एसआईएसए की संयुक्त डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2025 में देश के बैंकिंग, बीमा, भुगतान और अन्य वित्तीय संस्थानों पर करीब 29 लाख साइबर हमले दर्ज किए गए.

वर्ष 2021 में यह संख्या लगभग 14 लाख थी. यानी चार वर्षों में साइबर हमलों में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसने देश की वित्तीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का वित्तीय क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में 1.6 गुना अधिक साइबर हमलों का सामना कर रहा है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्था में डेटा सेंधमारी या साइबर घुसपैठ का पता लगाने और उसे पूरी तरह नियंत्रित करने में औसतन 263 दिन लग रहे हैं. इस लंबे समय के दौरान साइबर अपराधी संवेदनशील वित्तीय डेटा तक पहुंच बना सकते हैं और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं.

रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा की कई कमजोरियों को भी उजागर किया गया है. इनमें सिस्टम का कमजोर डिजाइन, सुरक्षा नियमों का रियल-टाइम में लागू न होना, बैंकिंग एप्लिकेशन और एपीआई की निगरानी में कमी तथा साइबर हमलों के दौरान स्वचालित प्रतिक्रिया तंत्र का अभाव प्रमुख कारण बताए गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि कई संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पारंपरिक मॉडल पर आधारित है, जबकि साइबर अपराधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर लगातार नए तरीके से हमले कर रहे हैं.

पीएफ वेतन सीमा बढ़ाने की मांग पर फैसला टला

नई दिल्ली, 14 जुलाई. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग पर फिलहाल कोई फैसला नहीं होगा. केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को टालते हुए कहा है कि सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही इस पर आगे बढ़ा जाएगा.

सरकार का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में वेतन सीमा बढ़ाने से कंपनियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा.

श्रमिक संगठन लंबे समय से ईपीएफ कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके. हालांकि सरकार का कहना है कि नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद उद्योगों का अनुपालन खर्च पहले ही काफी बढ़ चुका है. विशेष रूप से आईटी क्षेत्र ने नए नियमों के पालन पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त खर्च किया है. सरकार के अनुसार, यदि वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों का मासिक ईपीएफ अंशदान बढ़ जाएगा.

पश्चिम एशिया संकट की अर्थव्यवस्था मजबूत

विदेशी मुद्रा भंडार, मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र बने सहारा

महंगाई व रोजगार पर सतर्क रहने की जरूरत

नई दिल्ली, 14 जुलाई. पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव, समुद्री परिवहन में बाधाएं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव जैसी चुनौतियों के बीच भी भारत ने अपनी आर्थिक स्थिरता बनाए रखी है.

हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन विश्व बैंक समेत कई वैश्विक संस्थानों का मानना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा. पश्चिम एशिया संकट का सबसे अधिक असर कच्चे तेल, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम पर पड़ा. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर महंगाई, उद्योगों की लागत और चालू खाते पर पड़ता है.

हालांकि युद्धविराम और क्षेत्रीय तनाव में कमी आने से समुद्री परिवहन तथा ऊर्जा बाजार पर दबाव धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिससे भारतीय उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू मांग बनी हुई है. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश के पास 723.8 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो एक वर्ष से अधिक के आयात के लिए पर्याप्त माना जाता है.

खेती की जमीन बेचने पर हर बार टैक्स नहीं

नई दिल्ली, 14 जुलाई आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान सबसे ज्यादा भ्रम कृषि भूमि बेचने से होने वाली आय को लेकर रहता है. आम धारणा है कि खेती से जुड़ी हर आय पूरी तरह टैक्स मुक्त होती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. आयकर कानून के अनुसार, खेती की जमीन बेचने पर टैक्स लगेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन ग्रामीण कृषि भूमि है या शहरी कृषि भूमि. इसलिए जमीन बेचने के बाद आईटीआर में सही जानकारी देना बेहद जरूरी है. आयकर अधिनियम के तहत कृषि भूमि को दो श्रेणियों में बांटा गया है. ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत संपत्ति (कैपिटल एसेट) नहीं माना जाता. ऐसे में इस जमीन की बिक्री से होने वाला लाभ पूरी तरह टैक्स मुक्त होता है.

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE
Ke Saath Zimmedari Lagey Pyaari
Trusted by over 20 crore Indians in 25 YEARS

रिटायरमेंट की तैयारी अपनी शर्तों पर

आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड पेंशन सेविंग्स से मिलेगी उम्रभर आर्थिक सुरक्षा

भोपाल, 14 जुलाई. भारत की आबादी में तेजी से बदलाव आ रहा है. आज देश दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की संख्या भी तेजी से बढ़ने वाली है.

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार, वर्ष 2036 तक देश का हर सातवाँ व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा और उनकी संख्या बढ़कर करीब 23 करोड़ तक पहुँच जाएगी. पहले के मुकाबले लोगों में जीवन की प्रत्याशा काफी बढ़ी है. वहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह परिवार या अगली पीढ़ी पर निर्भर रहने का चलन भी धीरे-धीरे बदल रहा है. ऐसे में, रिटायरमेंट की पहले से योजना बनाना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि समय की जरूरत बन गया है.

इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आईसी आईसीआई प्रू गोल्ड पेंशन सेविंग्स की पेशकश की है. यह बोनस से जुड़ा पेंशन प्लान है, जिसे सुरक्षा और लचीलेपन दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस प्लान के जरिए ग्राहक रिटायरमेंट के लिए धीरे-धीरे एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं. इसमें निवेश की गई पूँजी सुरक्षित रहती है. किसी बड़ी जरूरत, जीवन की महत्वपूर्ण परिस्थितियों या गंभीर बीमारी के समय आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है, ताकि जरूरत के समय पैसों की कमी न हो परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी बनी रहे.

इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए, 40 वर्षीय प्रतीक हर साल 1.5 लाख रुपए 10 साल तक इस प्लान में निवेश करते हैं. ऐसे में, 60 साल की उम्र तक 8% सालाना रिटर्न के अनुमान पर उनका रिटायरमेंट फंड करीब 44 लाख रुपए हो सकता है. वहीं, 4% सालाना रिटर्न के अनुमान पर यह राशि करीब 25 लाख रुपए होगी.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर विकास गुप्ता ने कहा, 'हमारा मानना है कि रिटायरमेंट जिंदगी का ऐसा पड़ाव होना चाहिए, जिसे लोग खुशी के साथ जी सकें, न कि पैसों की चिंता के साथ. आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड पेंशन सेविंग्स को इसी सोच के साथ तैयार किया गया है. यह प्लान बोनस के जरिए फंड बढ़ाने का मौका देता है और जरूरत पड़ने पर बड़ी जीवन संबंधी परिस्थितियों या गंभीर बीमारी के दौरान पैसे निकालने की सुविधा भी प्रदान करता है.

महंगी एलपीजी के बीच गैस बचत नीति की मांग

सरकार से पहली 'एलपीजी दक्षता नीति' लागू करने की अपील

नई दिल्ली, 14 जुलाई रसोई गैस (एलपीजी) की लगातार बढ़ती कीमतों और वैश्विक स्तर पर सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच देश में पहली बार 'एलपीजी दक्षता नीति लागू करने की मांग उठी है.

गैस वितरण कंपनी पुणे गैस ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर एलपीजी के अधिक प्रभावी, सुरक्षित और किफायती उपयोग के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की अपील की है. कंपनी का कहना है कि केवल गैस की उपलब्धता बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उपलब्ध एलपीजी का कम से कम बर्बादी के साथ बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना भी समय की जरूरत है. कंपनी के अनुसार, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता का असर एलपीजी की कीमतों पर भी पड़ा है.

इस वर्ष की शुरुआत में करीब 1,884 रुपये में मिलने वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब लगभग 3,100 रुपये तक पहुंच गया है. इससे होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, लॉन्ड्री, एमएसएमई और अन्य छोटे-बड़े उद्योगों की परिचालन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. हालांकि सरकार की कोशिशों से देश में एलपीजी की आपूर्ति बनी हुई है.

लगातार 18वें साल देश का भरोसेमंद ब्रांड बना टाटा

नई दिल्ली, 14 जुलाई देश के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की नई रैंकिंग में टाटा समूह ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी है. ब्रांड फाइनेंस की 'इंडिया 100-2026' रिपोर्ट के अनुसार, टाटा समूह लगातार 18वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है.

इस दौरान कंपनी की ब्रांड वैल्यू में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और यह बढ़कर 33.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है.

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से शेयर बाजारों में गिरावट

मुंबई, 14 जुलाई पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट रही और बीएसई का सेंसेक्स एक सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ.

सेंसेक्स पिछले कारोबारी दिवस के मुकाबले 344 अंक नीचे खुला और पूरे दिन लाल निशान में रहा. अंत में यह 561.46 अंक (0.72 प्रतिशत) लुढ़ककर 77,054.94 अंक पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 158.95 अंक यानी 0.66 प्रतिशत नीचे 24,052.05 अंक पर बंद हुआ. यह दोनों प्रमुख सूचकांकों का 09 जुलाई के बाद का निचला स्तर है.

अमेरिका और ईरान के बीच हमले एक बार फिर शुरू हो गये हैं. अमेरिका जहां सीधे ईरान को निशाना बना रहा है, वहीं ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है. इससे बाजार में निवेश धारणा कमजोर हुई है. घरेलू स्तर पर प्रमुख सूचकांकों के साथ वृहत बाजार में भी गिरावट रही.

समाचार विशेष

क्या करेगी 15 लाख की फौज, युद्ध या मौज!

जयपुर. राजस्थान कांग्रेस अब पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि हाईटेक टैक्नॉलोजी से अपनी रणनीति बना रही है. वह 'डेटा' 'डिजिटल मॉनिटरिंग' और 'रियल टाइम रिपोर्ट कार्ड' के जरिये न केवल संगठन को एक सूत्र में पिरो रही है बल्कि 'कॉर्पोरेट स्टाइल मैनेजमेंट मॉडल' पर चलाने का दावा भी कर रही है.

राजस्थान कांग्रेस के इस मॉडल से उसकी टॉप लीडरशिप भी खासा इम्प्रेस है. वह गाहे-बगाहे अन्य राज्यों की पीसीसी को राजस्थान से सीख लेने की नसीहत भी देती है. पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के मॉडल का मुरीद हो रहा है. राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि उनकी 15 लाख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की फौज चुनावी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है. दिल्ली में बैठे पार्टी नेतृत्व को अब जयपुर से केवल राजनीतिक रिपोर्ट नहीं बल्कि डिजिटल डेटा, लाइव एक्टिविटी अपडेट, टास्क रिपोर्ट और बूथ स्तर तक की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम भेजा जा रहा है. कांग्रेस के भीतर इसे 'नया संगठनात्मक मॉडल' माना जा रहा है, जहां कार्यकर्ता की सक्रियता भाषणों से नहीं बल्कि उसके डिजिटल फुटप्रिंट से मापी जा रही है. एआईसीसी के नये शुरू किए गए 'कनेक्ट पोर्टल सिस्टम' पर इन सभी फार्मूलों पर काम करने की वजह से राजस्थान पीसीसी की ओर से टास्क मैनेजमेंट के मामले में 'नंबर वन' होने का दावा किया जा रहा है. राजस्थान पीसीसी का एसआईआर मॉडल तो कई राज्यों में हू-ब-हू लागू करने के लिए यहां के लोगों की ओर से उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है.

दरअसल, कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान समेत सभी राज्यों के संगठनात्मक कामकाज का छह अहम बिंदुओं पर रिव्यू शुरू किया है. यह रिपोर्ट सीधे कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जा रही है. लेकिन राजस्थान इस रिव्यू में इसलिए अलग नजर आ रहा है.

कैसे तैयार किया जा रहा है 'डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड

सूत्रों के मुताबिक 'डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड' तैयार किया जा रहा है. इसके लिए केवल रिपोर्ट भेजना ही पर्याप्त नहीं है. हर गतिविधि के साथ फोटो, वीडियो और अन्य डिजिटल एविडेंस भी अपलोड किए जाते हैं. इससे हाईकमान के पास जमीन पर हुई गतिविधियों का 'डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड' तैयार हो रहा है. पार्टी नेताओं का दावा है कि अब एक क्लिक पर राजस्थान कांग्रेस के लगभग 15 लाख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का डेटा देखा जा सकता है.

क्या खत्म हो रही आरएलडी - टिकैत की दूरी?

युद्धवीर सिंह की एंट्री से बढ़ी सियासी सरगर्मी

मेरठ. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में हाल फिलहाल में हुए घटनाक्रम ने नई सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया है. भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह को राष्ट्रीय लोकदल के संसदीय बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए जाने के चर्चा का बाजार गरमा गया है. इसे आरएलडी और टिकैत बंधुओं के बीच रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

संसदीय बोर्ड की बुधवार को दिल्ली में हुई पहली बैठक में भी बीकेयू नेता को जयंत ने बगल में बिठाकर खास अहमियत देने के तौर पर देखा जा रहा हैं. ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि क्या आरएलडी और टिकैत बंधुओं के बीच की दूरी खत्म हो रही हैं. अगर ऐसा है तब 2027 में चुनाव में रालोद को सियासी मजबूती मिलने की सभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है.

दरअसल, रालोद ने अपने संसदीय बोर्ड का गठन किया हैं. उसने पूर्व सांसद केसी त्यागी अध्यक्ष बनाए गए हैं. जयंत चौधरी समेत कई दिग्गजों को आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया है. उसमें यूं तो कई नाम रालोद से बाहर के हैं, लेकिन असल में एक नाम युद्धवीर सिंह को शामिल करने पर हर कोई अलग मायने मिकाल रहा है. दरअसल, यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब हाल के महीनों में दोनों पक्षों (रालोद-टिकैत बंधुओं) के बीच सार्वजनिक तल्खियां देखने को मिली थीं.

अजित सिंह भी दिखे थे साथ

दरअसल, रालोद सियासी दल है. बीकेयू गैर सियासी संगठन है. दोनों का मजबूत कार्यक्षेत्र वेस्ट यूपी है. दोनों के मुखिया सजातीय (जाट) हैं. किसानों के हक के लिए दोनों आवाज बुलंद करते रहे हैं. जिस तरह फिलहाल चौधरी जयंत सिंह की तरफ से बीकेयू टिकैत को तवज्जो दी जा रही है, ऐसे ही संकट के समय में जयंत के पिता चौधरी अजित सिंह भी टिकैट परिवार के साथ खड़े हो जाते थे.

पीके की चिंता में बिहार भाजपा

पटना. बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट का नतीजा चाहे जो हो पर इतना कहा जा सकता है कि भाजपा को सबसे ज्यादा चिंता प्रशांत किशोर की सता रही है. सबसे पहले तो इस चिंता का पता तब चला, जब दूसरे कई राज्यों को छोड़ कर आनन फानन में बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान हुआ है.

साथ में मध्य प्रदेश और गुजरात की एक एक सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है. लेकिन अगर बांकीपुर जल्दी नहीं कराना होता तो उसे भी टाला जा सकता था. चूंकि अकेले बांकीपुर कराते तो मैसेज अलग जाता इसलिए दो सीट और जोड़ दिए. लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों की सीटों पर उपचुनाव नहीं कराया. ऐसा इसलिए हुआ ताकि प्रशांत किशोर को तैयारी का ज्यादा समय न मिले.

प्रशांत किशोर की भाजपा को कैसे चिंता है यह उम्मीदवार की घोषणा में भी दिखा. भाजपा ने पार्टी के एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अभिषेक सिन्हा को उम्मीदवार बनाया. वे कायस्थ समाज से आते हैं. बांकीपुर सीट पर पिछले नौ चुनाव से नितिन नबीन या उनके पिता नबीन किशोर सिन्हा जीते हैं.

विशेष | **भाजपा के नए अध्यक्षों पर विधानसभा चुनाव का दबाव**

क्षेत्रीय अध्यक्षों के सामने रिकॉर्ड सुधारने की चुनौती

लखनऊ. भाजपा ने विधान सभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति तो कर दी, लेकिन इससे चुनौतियां कम नहीं होने वाली. नए अध्यक्षों की चुनावों में कड़ी परीक्षा होगी. पिछली टीम में यानी 2023 में बने क्षेत्रीय अध्यक्षों का प्रदर्शन 2024 लोकसभा चुनाव में निराशाजनक रहा था, ऐसे में नए अध्यक्षों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव है.

खासकर जब विधान सभा चुनाव में सिर्फ सात माह बचे हैं और अध्यक्षों के पास क्षेत्रों में दौरा करने का भी समय नहीं होगा. चार और पांच जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन की जिला स्तर तक की इकाइयों को चुनावी लक्ष्य देकर उनकी चुनौती और बढ़ा दी है. भाजपा ने प्रदेश एवं जिला संगठन बनाने के लिए जातीय एवं सामाजिक समीकरणों में समन्वय साधने में लंबा वक्त लगाया. मोर्चो के चेहरों को लेकर भी कई चरणों में मंथन चला.

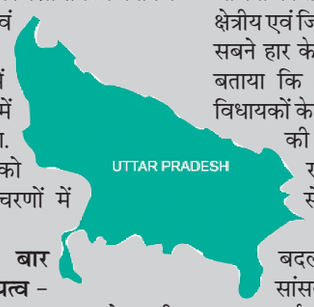

पहली बार संभालेंगे ये दायित्व - पार्टी ने पिछले माह 25 जून को काशी, ब्रज, गोरखपुर, पश्चिम क्षेत्र, कानपुर एवं अवध क्षेत्र के अध्यक्षों की घोषणा की, जिसमें सब पहली बार इस दायित्व को संभालेंगे. 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा. तत्कालीन क्षेत्रीय एवं जिलाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी गई. सबने हार के कारणों पर रिपोर्ट दी. यह बताया कि अंदरूनी कलह और कई विधायकों के असहयोग की वजह से पार्टी की सीटें घटकर लगभग आधी रह गईं. हार के बाद कई सीटों से बगावत के सुर भी उभरे. पार्टी ने माना कि संविधान बदलने के नैरेटिव, वर्तमान सांसदों के प्रति विरोध, कार्यकर्ताओं की उदासीनता एवं सपा के पीडीए फैक्टर के असर से कमल मुरझाया. संगठन में भी कोई धार नहीं दिखाई पड़ी. अब नए क्षेत्रीय अध्यक्षों के सामने सात माह के दौरान दर्जनों जिलों में भ्रमण, अभियानों का संचालन, क्षेत्र एवं जिलों की टीमों का निर्माण, प्रवासियों का ध्यान एवं बड़े नेताओं की जनसभा कराना है. उन्हें बैठकों में बताया जा चुका है कि पिछले लोकसभा चुनाव में विधान सभा वार परिणाम देखें तो भाजपा बड़े अंतर से हारी है.

35 पिछड़ी जातियों की गोलबंदी पर फोकस

लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश संगठन ने दलितों को साधने के लिए गांवों में जनसंपर्क किया. हर विधान सभा सीट पर पांच हजार से ज्यादा मतदाता वाली 35 पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने पर फोकस किया. जातीय आधार पर महापुरुषों का कैलेंडर बनवाया. सवर्ण वोटों की डोर को कसकर रखने का प्रयास किया. मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर इसका बढ़ चढ़कर प्रचार किया. महिला आरक्षण संशोधन विधेयक सदन में गिरने के बाद देशभर में प्रदर्शन किया. प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार एवं बाद में संगठन विस्तार में पीडीए का पूरा ध्यान रखा, लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी के प्रयासों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय अध्यक्षों को उठाना होगा, जिसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है.